



दैनिक

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

एक विश्वास....

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, रामपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।

शनि मंगल की युति से बना अशुभ योग ...8

सिद्धार्थनगर

रविवार ,05 अप्रैल 2026

वर्ष: 13 अंक : 108 पृष्ठ: 8

आमंत्रण मूल्य 2/-रुपया

सम्पादक : राजेश शर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश

8795951917, 9415163471

@budhakasandesh

budhakasandeshnews@gmail.com

www.budhakasandesh.com

उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला

ईरान की चेतावनी-रेडिएक्टिव रेडिएशन से तबाह होंगे खाड़ी देश

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शनिवार को पश्चिमी देशों के श्दोहरे मापदंडश की कड़ी निंदा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में संघर्ष की शुरुआत के बाद से चौथी बार इस्लामिक गणराज्य के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हुए हमलों पर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया में अंतर की तुलना

यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हुई शत्रुता पर की गई प्रतिक्रिया से की। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि क्या आपको यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हुई शत्रुता



याद है? इजराइल और अमेरिका ने हमारे बुशहर संयंत्र पर चार बार बमबारी की है। रेडियोधर्मी विकिरण से जीसीसी की राजधानियों में जीवन समाप्त होगा, तेहरान में नहीं। हमारे पेट्रोकेमिकल संयंत्रों पर हमले

वास्तविक उद्देश्यों को दर्शाते हैं। यह घटना शनिवार सुबह बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की परिधि के पास एक मिसाइल गिरने के बाद हुई, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। यह जानकारी ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम ने दी है। तसनीम समाचार एजेंसी के अनुसार, इस घटना में संयंत्र के मुख्य भागों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक सहायक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। समाचार एजेंसी के दावे के अनुसार, उत्पादन अप्रभावित रहा। बुशहर संयंत्र दक्षिणी ईरान में फारस की खाड़ी पर स्थित है

और यह देश का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ईरानी विदेश मंत्री ने ईरान में छह पेट्रोकेमिकल संयंत्रों को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी-इजरायली हवाई हमलों का भी जि्क किया। प्रेस टीवी के अनुसार, देश के दक्षिण-पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत में छह पेट्रोकेमिकल संयंत्रों को निशाना बनाकर किए गए इन हवाई हमलों में कम से कम पांच लोग घायल हुए। इसी बीच, एक अलग पोस्ट में अराघची ने चल रहे संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसे ईरान पर थोपा गया अवैध युद्ध बताया।

वैश्विक संकटों के बीच भारत ने दिखाई जबरदस्त मजबूती

जयशंकर ने गिनाई मोदी की कूटनीतिक उपलब्धियां

भारत ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर दोनों तरह की चुनौतियों का सफलतापूर्वक दिया कि पर उत्पन्न बड़े संकटों के बीच जिस तरह अपनी मजबूती बनाए रखी है, वह देश की बढ़ती ताकत और संतुलित नीतियों का प्रमाण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी संदर्भ में कहा कि भारत ने दुनिया में चल रहे उथल पुथल के दौर में न केवल खुद को संभाला बल्कि मजबूती के साथ आगे बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ में स्थित आईआईएम रायपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू और बाहरी सामना किया है। उन्होंने इस बात पर जोर



देश आज दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यह उपलब्धि अपने आप में बहुत बड़ी है। जयशंकर ने कहा कि बीते दस वर्षों में देश ने जो प्रगति की है, उसने समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। यही कारण है कि भारत में आशावाद की भावना देखने को मिलती है, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में यह भावना कमजोर पड़ती दिख रही है। उन्होंने कहा कि यह विश्वास आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा और भारत की विकास यात्रा को नई गति देगा।

सीएम योगी का एसपी पर तीखा हमला

उनकी सरकार में नकल माफिया को मिलता था बढ़ावा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने 2017 से पहले राज्य में शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा की थी। स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी स्कूलों में नकल को बढ़ावा देती थी और बच्चों के कल्याण की उसे कोई चिंता नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले क्या स्थिति थी? न तो शिक्षा सरकार के एजेंडे में थी, न ही गरीब बच्चों या किसी आम बच्चे की कोई चिंता थी, क्योंकि उनको



लोग नकल को बढ़ावा देते थे। इसके विपरीत, यूपी के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने स्कूली शिक्षा में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा प्रशासन ने बुनियादी शिक्षा परिषद के अंतर्गत नामांकित प्रत्येक बच्चे को ये व्यापक सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर

प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करते हैं। दोहरी इंजन वाली सरकार ने बुनियादी शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को ये सभी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की हैं। एक वर्ष में दो यूनिफॉर्म, एक बैग, किताबें, जूते, मोजे और एक खेटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा करते हुए शिक्षकों का मासिक वेतन 17,000 रुपये और शिक्षा मित्रों का 18,000 रुपये निर्धारित किया है, जो अप्रैल से ही प्रभावी होगा। बाद में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह समाज को आकार देने का एक शक्तिशाली माध्यम है।

एलपीजी की लंबी कतारें, खरगे बोले- सरकार की विदेश नीति की खामियों की सजा भुगत रही जनता

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कहा कि देश में गैस की कमी है और लोग लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने इस संकट का कारण सरकार की विदेश नीति की खामियों को बताया और कहा कि इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के चलते पश्चिम एशिया में तनाव के बीच गैस की कमी की समस्या उत्पन्न हुई है। बेंगलुरु में बोलते हुए खरगे ने कहा कि देश में गैस की समस्या है। लोग लंबी कतारों में फंसे हुए हैं। यह सबके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। सरकार को इस पर ध्यान देना



चाहिए। लेकिन वह ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उनकी विदेश नीति सही नहीं है। आज हम उनकी गलत विदेश नीति के कारण भुगत रहे हैं। इससे पहले, कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने जोर देकर कहा था कि घरेलू और सार्वजनिक परिवहन की जरूरतों के लिए गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है। सरकार ने इंडियनऑयल को वर्तमान 59.53 मीट्रिक टन से

दैनिक बिक्री बढ़ाने का निर्देश दिया है और निजी वितरकों को कालाबाजारी और अनधिकृत मूल्य वृद्धि के खिलाफ चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, जमाखोरी रोकने के लिए जिला स्तरीय निगरानी समितियां गठित की गई हैं। भारत सरकार ने शनिवार को जनता को आश्चर्य करते हुए देशभर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पेट्रोलियम जेली (पीजी) की पर्याप्त आपूर्ति की पुष्टि की। शुक्रवार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया कि उसके पांच किलोग्राम के फ्री ट्रेड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एफटीएल) सिलेंडर तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को लगातार आपूर्ति किए जा रहे हैं।

हिमंता का ओवैसी पर तीखा हमला, मिया समुदाय को बना रहे हैं हथियार



असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिरसा सरमा ने 4 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि एआईयूडीएफ के समर्थन में असम दौरे के दौरान उनके चुनावी भाषणों का मकसद राजनीतिक लाभ के लिए मिया समुदाय का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कांग्रेस

पर ऐसे बयानों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस ने चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने और मतदाताओं को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने के लिए ओवैसी को असम में भेजा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ओवैसी की भाषणों से आबादी के कुछ खास वर्गों को लामबंद करने की कोशिशें झलकती हैं। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ऐसे बयानों की आलोचना करने में विफल रही है और यूनस तमूली और यूनस अली जैसे लोगों से जुड़े विवादस्पद बयानों और घटनाओं पर चुप रही है।

एफसीआरए संशोधन विधेयक पर किरेन रिजिजू की कांग्रेस को चेतावनी, झूठ फैलाया तो बेनकाब करेंगे

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के बारे में फैलाई जा रही झूठ को सरकार बेनकाब करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में ईसाई मिशनरियों से बातचीत की गई है ताकि उनकी चिंताओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सके। एएनआई से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि हमने केरल में ईसाई मिशनरियों से बातचीत की है और उनकी चिंताओं को सुना है। हमें सवाल-जवाब और संवाद के माध्यम से मिलकर काम करने की जरूरत है। मंत्री ने दावा किया कि हमने सभी चिंताओं को सुना है और केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का इरादा किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ काम करने का नहीं है। अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस झूठ फैलाना जारी रखते हैं, तो हम उन्हें बेनकाब करेंगे। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार के तहत अल्पसंख्यकों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान को झटका!

यूई ने वापस मांगे 2 अरब डॉलर, युद्ध बना कारण

पहले से ही गंभीर आर्थिक बंदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। संयुक्त अरब अमीरात (नम) ने पाकिस्तान को दिए गए 2 अरब डॉलर (लगभग 17,000 करोड़ रुपये से अधिक) का कर्ज तुरंत चुकाने की मांग की है। शुक्रवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने इस महीने के अंत तक यह भारी-भरकम राशि लौटाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, यूई ने यह राशि पाकिस्तान को भुगतान संतुलन के समर्थन के लिए प्रदान की थी और यह हाल तक आगे बढ़ाई जा रही थी। यूई ने हाल



और अमेरिका-इजराइल के ईरान के साथ युद्ध के मद्देनजर यह पैसा तुरंत वापस मांगा है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह राशि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सुरक्षित जमा के तौर पर रखी गई थी। पाकिस्तान यह रकम इस महीने के अंत तक यूई को लौटा देगा। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा

मंडार पर दबाव पाकिस्तान के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। 2 अरब डॉलर की इस निकासी से पाकिस्तान के लिए गिरावट आ सकती है। मुद्रा का अवमूल्यन: विदेशी मुद्रा मंडार घटने से पाकिस्तानी रुपया और कमजोर हो सकता है। महंगाई: डॉलर की कमी से आयात महंगा होगा, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। IMF की शर्तें: पाकिस्तान पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से नए राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है, और मंडार में कमी उसकी साख पर असर डाल सकती है।

यूसीसी पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान-

कुछ संगठन भारत को इस्लामी देश बनाना चाहते हैं

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम संगठन भारत को एक इस्लामी राज्य में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने शनिवार को बिहार के बेगुसराय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं। मंत्री ने कहा आगे कहा कि मुस्लिम संगठन भारत को इस्लामी देश बनाना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। एक राष्ट्र, एक कानून, प्रध

ानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। उनकी ये टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा हाल ही में असम में यूसीसी लागू करने के वादे के बीच आई हैं। भाजपा ने राज्य में सत्ता में वापसी होने पर इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया है। घोषणापत्र बुधवार को जारी किया



गया, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिरसा सरमा ने उत्तराखंड और गुजरात के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए भाजपा के

मूल एजेंडे को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री सरमा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और कथित श्लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों या आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होगा। सरमा ने कहा कि हम असम को सबसे उज्ज्वल राज्य बनाना चाहते हैं। हम आश्रित राज्य नहीं बनना

चाहते हैं हम देश के निर्माण में हिस्सा लेना चाहते हैं। संकल्प पत्र में हमने 31 वादे किए हैं। हम छठी अनुसूची और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर असम में यूसीसी लागू करेंगे। हम लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। हम असम को बाढ़ मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे और पहले दो वर्षों में 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा और मतगणना

केरल में राहुल गांधी का एलडीएफ पर बड़ा हमला, बोले-

चुनाव बाद वामपंथ नहीं बचेगा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) पर अपनी मूल विचारधारा को त्यागने का आरोप लगाया और कहा कि आगामी चुनावों के बाद एलडीएफ में कुछ भी वामपंथी नहीं बचेगा। 4 अप्रैल को केरल के अलापुझा में एक जनसभा में बोलते हुए गांधी ने एलडीएफ की सिद्धांतों से समझौता करने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि एलडीएफ कई सालों से हमारे विरोधी रहे हैं, हमने उनसे लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन कई सालों तक वे कुछ ऐसे विचारों के लिए खड़े

रहे जिनसे हम सहमत नहीं थे, और हमने उन्हीं विचारों के आधार पर उनका विरोध किया। लेकिन वे किसी बात के लिए खड़े थे, और उसी के प्रतीक के रूप में उनके संगठन के नाम में श्वामपंथी शब्द है। राहुल ने सवाल किया कि एलडीएफ का मतलब क्या है? वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। सच कहूं तो, वाम मोर्चे में कुछ भी श्वामपंथी नहीं है, और चुनाव के बाद वाम मोर्चे में कुछ भी श्वामपंथी नहीं बचेगा। गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ



(एलडीएफ) के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केरल की सांप्रदायिक सरकार को एक गुप्त शक्ति प्रभावित कर रही है, जो उनके अनुसार संविधान को नकारती है और जनता पर हमला करती है। उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे

नेता को जो बात परेशान कर रही है, वह यह है कि उनकी नीतियां अब वामपंथी नहीं रहें। उन्हें और वाम मोर्चे के कई कार्यकर्ताओं को जो बात परेशान कर रही है, वह यह है कि आज एलडीएफ सरकार को एक गुप्त शक्ति चला रही है। यह गुप्त शक्ति सांप्रदायिक है, भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करती, भारत की जनता को बांटती है, उन पर हमला करती है, उन्हें अपमानित करती है, और केरल में हर कोई देख सकता है कि अब भाजपा, आरएसएस और वाम मोर्चे

(सीपीएम) के बीच संबंध हैं। गांधी ने वाम मोर्चे (एलडीएफ) को अवसरवादी नेताओं का समूह बताते हुए कहा कि वे सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और भाजपा एवं आरएसएस से सहायता लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जो इन विचारों से सहमत नहीं हैं, खुद को धोखा दिया हुआ और आहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वाम मोर्चे के अधिकांश नेता अवसरवादी हैं। यह समझिएरु कुछ अवसरवादी नेता सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे।



नए शैक्षिक सत्र के साथ ‘स्कूल चलो अभियान’ का शुभारंभ, बच्चों को किया गया प्रेरित

दैनिक बुद्ध का संदेश



सिद्धार्थनगर। नए शैक्षिक सत्र के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘स्कूल चलो अभियान’ का विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ल्वहप ।कपजलंदंजी ने वाराणसी से इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय धौरीकुइयां में भी किया गया, जहां

जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में बच्चों ने इसे देखा और सुना। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कपिलवस्तु विधायक ौलउंकीदप तैप मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार एवं खंड शिक्षा अधिकारी राम कुमार सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक

बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। इस अवसर पर विधायक श्यामधनी राही ने बच्चों को पुस्तकें वितरित कर उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है और सरकार हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही अभिभावकों से

अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। शिक्षक—शिक्षिकाओं ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और नए सत्र में बेहतर उपस्थिति व परिणाम के लिए संकल्प लिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि ‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत जनपद के सभी विद्यालयों में

नामांकन बढ़ाने, ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ने तथा शैक्षिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता अमित कुमार शुक्ला, प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र, शिक्षक अनूप कुमार, वीरेंद्र चौधरी, रंजना, शिक्षा मित्र बेचन प्रसाद, बीनू पांडेय तथा रसोइयां राजमती, प्रमिला एवं इंद्रावती सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न, गुणवत्ता सुधार व डिजिटल शिक्षा पर जोर

दैनिक बुद्ध का संदेश



सिद्धार्थनगर। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रशिक्षण संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार गोविंद जायसवाल ने की। बैठक में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन, सहायक निदेशक सुमन शा तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान के अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में संचालित शैक्षिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना रहा। संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने, शिक्षण पद्धति को रोचक एवं प्रभावी बनाने तथा डिजिटल माध्यमों के अधिकतम उपयोग पर विशेष बल दिया। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने जनपद

में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में समय से पठन—पाठन सुनिश्चित किया जाए तथा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का समय—समय पर मूल्यांकन करने के निर्देश भी दिए। बैठक में ‘सारथी’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीट/जेईई की तैयारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जानपुर द्वारा कराए जाने की जानकारी दी गई तथा सभी विद्यार्थियों का अपार आईडी बनवाने के निर्देश भी दिए गए। सहायक निदेशक सुमन शा ने शिक्षकों को नवीन कराने पर जोर देते हुए कहा कि कौशल विकास हेतु नियमित

प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षक आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाकर बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। केंद्रीय हिंदी संस्थान के अधिकारियों ने हिंदी भाषा के प्रचार—प्रसार एवं शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए और भाषा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु नवाचार अपनाने पर बल दिया। बैठक के अंत में संयुक्त सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय को भी आवश्यक बताया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्राचार्य एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

थाना कोतवाली लोटन पुलिस दो अभियुक्तों गिरफ्तार कर भेजा जेल

दैनिक बुद्ध का संदेश लोटन/सिद्धार्थनगर।थाना लोटन क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा संख्या 07/2026 धारा 64(2)छ, 64(2)५, 85, 88, 352, 115(2), 3(5) ट.छ. े एवं धारा 5/6 च्छै एकट तथा धारा 9/10/11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में दर्ज मामले में दो मुख्य अभियुक्तों को आज सफलतापूर्वक गिरतार कर लिया गया है। यह मुकदमा मूल रूप से मुंबई (थाना अंबोली) में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में संबंधित क्षेत्राधिकार के अनुसार थाना लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर में स्थानांतरित किया गया था। अभियुक्त धीरज यादव (पुत्र स्वर्गीय सुखराज यादव, उम्र करीब 41 वर्ष) ने अपने पुत्र संजय यादव (उम्र करीब 22 वर्ष)

का विवाह एक नाबालिग बालिका से कराया था। विवाह के बाद अभियुक्त धीरज यादव ने उक्त नाबालिग बालिका के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसे मुंबई ले गया। वहाँ बालिका गर्भवती हो गई। इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा बालिका को नाबालिग पाए जाने पर थाना अंबोली, मुंबई में मुकदमा दर्ज हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही दोनों अभियुक्त फरार हो गए थे। दोनों अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहे थे। उनकी गिरतारी हेतु पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा दोनों अभियुक्तों पर 25,000/— रुपये (पच्चीस हजार रुपये) प्रत्येक, कुल 50,000/— रुपये (पचास हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज थानाध्यक्ष कोतवाली

लोटन दिनेश कुमार सरोज की टीम, जिसमें उपनिरीक्षक दिलीप कुमार सोनी, हेड कांस्टेबल सुनील दत्त, हेड कांस्टेबल संजय गुप्ता एवं कांस्टेबल विनय राजभर शामिल थे, ने मुखबिरी के सूचना पर जिला अस्पताल के पास धीरज यादव को पकड़ा। उसके बयान के आधार पर उसके पुत्र संजय यादव को भी गिरतार किया गया। माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त होने के उपरांत दोनों अभियुक्तों को जिला कारागार भेज दिया गया है। यह गिरतारी जनपद पुलिस की निरंतर निगरानी और प्रभावी टीम वर्क का परिणाम है। नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार, यौन शोषण और बाल विवाह जैसे गंभीर अपराधों पर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है।

कार्यालय : ग्राम पंचायत- केरोना वि.ख.- रूधौली, जनपद- बस्ती

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत— **केरोना** विकसित भारत गारन्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G/पंचम वित्त/सष्ठम वित्त/15 वां/16 वां वित्त/स्वच्छ भारत निशन/केन्द्रीय वित्त आयोग विधायक निधि/सांसद निधि/आगनबाड़ी/सामुदायिक शौचालय/प्राथमिक विद्यालय पर शौचालय/पंचायत भवन/अन्त्योष्टि स्थल विकास निर्माण कार्य/छट पूजा घाट/खेल मैदान/वाटर सप्लाई एवं अन्य निधि के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 में स्वीकृत कार्यये जाने वाले कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईट इन्टरलाकिंग, ईट, ईट टुकड़ा, महीन बालू, सिमेंट, मोरंग, बालू व वर्मी कम्पोस्ट एवं हयूम पाईप सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर गिट्टी, सोलर लाईट स्ट्रीट लाईट ठेला कुदाल झाड़ू ब्लीचिंग पाउडर चूना कूड़ादान फांगिंग मशीन झाड़ी झंखाड कटाई/नाली सफाई एवं कूड़ा निस्तारण कार्य एसएलएलडब्ल्यूएम०/ई०बी०आर० के तहत प्लास्टिक बैग, गणक स्थायी कचरा समाग्री इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत ईट की गिट्टी इत्यादि सामाग्री से सम्बन्धित आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म ईट भटटा मालिक/आपूर्ति कर्ता दिनांक 10/04/2026 अपराहन 10 बजे तक आपूर्ति हेतू निविदा दर पर एवं वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत **केरोना** के निविदा बाक्स में डाल सकते है। निविदा दिनांक 10/04/2026 को 02 बजे तक गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताए पूर्ण की जायेगी। धरोहर की धन राशि 2000 रु० होगी। **नियम व शर्त :-** 1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाों उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयेरन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से नि्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़धकर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों सचिवों सदस्यों बी.डी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरे प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडी एवं एनएससी/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सोहना** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत **केरोना** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/— रुपये पर ही स्वीकार किया जायेगा।

रंजना देवी	विनोद कुमार जासवाल
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष	ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत-केरोना	ग्राम पंचायत-केरोना
वि.ख. - रूधौली	वि.ख. - रूधौली

कार्यालय : ग्राम पंचायत- पिपरपातीखुर्द वि.ख.- रूधौली, जनपद- बस्ती

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत— **पिपरपाती खुर्द** विकसित भारत गारन्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G/पंचम वित्त/सष्ठम वित्त/15 वां/16 वां वित्त/स्वच्छ भारत निशन/केन्द्रीय वित्त आयोग विधायक निधि/सांसद निधि/आगनबाड़ी/सामुदायिक शौचालय/प्राथमिक विद्यालय पर शौचालय/पंचायत भवन/अन्त्योष्टि स्थल विकास निर्माण कार्य/छट पूजा घाट/खेल मैदान/वाटर सप्लाई एवं अन्य निधि के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 में स्वीकृत कार्यये जाने वाले कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईट इन्टरलाकिंग, ईट, ईट टुकड़ा, महीन बालू, सिमेंट, मोरंग, बालू व वर्मी कम्पोस्ट एवं हयूम पाईप सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर गिट्टी, सोलर लाईट स्ट्रीट लाईट ठेला कुदाल झाड़ू ब्लीचिंग पाउडर चूना कूड़ादान फांगिंग मशीन झाड़ी झंखाड कटाई/नाली सफाई एवं कूड़ा निस्तारण कार्य एसएलएलडब्ल्यूएम०/ई०बी०आर० के तहत प्लास्टिक बैग, गणक स्थायी कचरा समाग्री इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत ईट की गिट्टी इत्यादि सामाग्री से सम्बन्धित आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म ईट भटटा मालिक/आपूर्ति कर्ता दिनांक 13/04/2026 अपराहन 10 बजे तक आपूर्ति हेतू निविदा दर पर एवं वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत **पिपरपाती खुर्द** के निविदा बाक्स में डाल सकते है। निविदा दिनांक 13/04/2026 को 01 बजे तक गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताए पूर्ण की जायेगी। धरोहर की धन राशि 2000 रु० होगी। **नियम व शर्त :-** 1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाों उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयेरन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़धकर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों सचिवों सदस्यों बी.डी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरे प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत त बैंकों के एफडी एवं एनएससी/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पिपरपाती खुर्द** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत **पिपरपाती खुर्द** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/— रुपये पर ही स्वीकार किया जायेगा।

श्रीमती सरातुननिशा	शैलेन्द्र त्रिपाठी
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष	ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत-पिपरपाती खुर्द	ग्राम पंचायत-पिपरपाती खुर्द
वि.ख. - रूधौली	वि.ख. - रूधौली

कार्यालय : ग्राम पंचायत- महदेवा बुजुर्ग वि.ख.- नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत— **महदेवा बुजुर्ग** विकसित भारत गारन्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G/पंचम वित्त/सष्ठम वित्त/15 वां/16 वां वित्त/स्वच्छ भारत निशन/केन्द्रीय वित्त आयोग विधायक निधि/सांसद निधि/आगनबाड़ी/सामुदायिक शौचालय/प्राथमिक विद्यालय पर शौचालय/पंचायत भवन/अन्त्योष्टि स्थल विकास निर्माण कार्य/छट पूजा घाट/खेल मैदान/वाटर सप्लाई एवं अन्य निधि के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 में स्वीकृत कार्यये जाने वाले कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईट इन्टरलाकिंग, ईट, ईट टुकड़ा, महीन बालू, सिमेंट, मोरंग, बालू व वर्मी कम्पोस्ट एवं हयूम पाईप सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर गिट्टी, सोलर लाईट स्ट्रीट लाईट ठेला कुदाल झाड़ू ब्लीचिंग पाउडर चूना कूड़ादान फांगिंग मशीन झाड़ी झंखाड कटाई/नाली सफाई एवं कूड़ा निस्तारण कार्य एसएलएलडब्ल्यूएम०/ई०बी०आर० के तहत प्लास्टिक बैग, गणक स्थायी कचरा समाग्री इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत ईट की गिट्टी इत्यादि सामाग्री से सम्बन्धित आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म ईट भटटा मालिक/आपूर्ति कर्ता दिनांक 13/04/2026 अपराहन 2 बजे तक आपूर्ति हेतू निविदा दर पर एवं वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत **महदेवा बुजुर्ग** के निविदा बाक्स में डाल सकते है। निविदा दिनांक 13/04/2026 को 3 बजे तक गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताए पूर्ण की जायेगी। धरोहर की धन राशि 2000 रु० होगी। **नियम व शर्त :-** 1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाों उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयेरन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़धकर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों सचिवों सदस्यों बी.डी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरे प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत त बैंकों के एफडी एवं एनएससी/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **महदेवा बुजुर्ग** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत **महदेवा बुजुर्ग** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/— रुपये पर ही स्वीकार किया जायेगा।

श्रीमती रेहाना खातून	प्रीति गुप्ता
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष	ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत-महदेवा बुजुर्ग	ग्राम पंचायत-महदेवा बुजुर्ग
वि.ख. - नौगढ़	वि.ख. - नौगढ़

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय भेजे गए

दैनिक बुद्ध का संदेश

खेसरहा / सिद्धार्थनगर। पर, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत थाना खेसरहा पुलिस ने कुमार प्रसाद के मार्गदर्शन एवं



आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश

क्षेत्राधिकारी बाँसी शुबेन्दु सिंह के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, मुकदमा संख्या 43 / 2026 धारा 108, 85

बीएनएस के तहत वांछित अभियुक्त शिवदयाल पुत्र बेचन एवं बेचन उर्फ कृष्ण मुरारी पुत्र स्व. जगदीश, निवासी महुआपुर थाना खेसरहा को धर्मसिंहवा मोड़ कलनाखोर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। मामले के अनुसार, ग्राम पारानानकार थाना जोगिया उदयपुर निवासी अजय प्रसाद की 31 वर्षीय पुत्री प्रीती ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर 2 अप्रैल 2026 को अपने कमरे में साड़ी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में मृतका के पिता की तहरीर पर थाना खेसरहा में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

श्री सहस्त्रचण्डी महायज्ञ एवं राम कथा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

दैनिक बुद्ध का संदेश



बांसी / सिद्धार्थनगर। वासंतीय नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर पालिका बांसी क्षेत्र में आयोजित श्री सहस्त्रचण्डी महायज्ञ, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री राम कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कार्यक्रम का आयोजन राप्ती तट स्थित श्री नव दुर्गा राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन के संयोजक आचार्य इन्द्रासन मिश्र,

व्यवस्थापक पंडित ऋषि शुक्ला तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथा व्यास पंडित रवीन्द्र शास्त्री के सानिध्य में 28 मार्च 2026 से कथा का शुभारंभ हुआ, जो निरंतर जारी है। कार्यक्रम का पूर्णाहुति एवं कथा समापन 05 अप्रैल 2026, रविवार को होगा। शनिवार को आयोजित कथा में कथा व्यास पंडित रवीन्द्र शास्त्री ने श्री राम विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु

भाव-विभोर हो उठे। कथा के दौरान पूरा पंडाल भक्ति रस में डूबा नजर आया। इस अवसर पर इन्द्रासन मिश्र, राम किंकर त्रिपाठी, बृजेश कुमार पाण्डेय, ओम प्रकाश पाठक, कालिका प्रसाद त्रिपाठी, सच्चिदानन्द त्रिपाठी, प्रेम शंकर शुक्ल, भोलानाथ पाठक, अनन्त उपाध्याय सहित सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर कथा का श्रवण किया।

गैस सिलेंडर दूसरे को बेचने का आरोप, उपभोक्ता ने की कार्रवाई की मांग

दैनिक बुद्ध का संदेश

उसका बाजार / सिद्धार्थनगर। श्याम सुंदर भारत गैस एजेंसी पर उपभोक्ता का गैस सिलेंडर दूसरे व्यक्ति को बेचने का आरोप लगा है। इस संबंध में उपभोक्ता किसमती देवी ने शनिवार को जिला पूर्ति अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में किसमती देवी ने बताया कि उन्होंने 19 मार्च को ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक किया था, जिसकी डिलीवरी 21 मार्च को होनी थी, लेकिन अब तक उन्हें सिलेंडर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बुकिंग की धनराशि पर मिलने वाली सब्सिडी उनके खाते में आ चुकी है, इसके बावजूद गैस न मिलने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बुक किया गया गैस सिलेंडर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया है। इस मामले में पीड़िता ने जिला पूर्ति अधिकारी से जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

बीएचएनडी दिवस पर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर दिया जोर

दैनिक बुद्ध का संदेश



सिद्धार्थनगर। बीएचएनडी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस) के अवसर पर

की जांच की तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा संचालित सैम (गंभीर कुपोषित) एवं मैम

उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा बहुओं को निर्देशित किया कि टीकाकरण से एक दिन पूर्व घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सूचित करें। एएनएम को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी बच्चा या गर्भवती महिला जांच और टीकाकरण से वंचित न रहे। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को विन्धित कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना



जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन ने जनपद के विभिन्न गांवों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विकास खंड खुनियांव के ग्राम रमवापुर कली, पशुपतिनगर व नरकटहा (विकास खंड बांसी) तथा मसिना (विकास खंड जोगिया) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं के रजिस्टर

(मध्यम कुपोषित) बच्चों के रजिस्टर का अवलोकन किया। साथ ही बच्चों को दिए जा रहे पोषाहार वितरण की जानकारी भी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बीएचएनडी दिवस के अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम अनिवार्य रूप से कराए जाएं तथा पात्र लाभार्थियों को समय से पोषाहार उपलब्ध कराया जाए।

योजना का लाभ पात्र महिलाओं को दिलाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान ग्राम रमवापुर कली में जिलाधिकारी ने स्वयं गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर संबंधित एमओआईसी, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मंगराव के दो होनहार छात्रों ने स्वा इतिहास, अटल आवासीय विद्यालय में चयन

दैनिक बुद्ध का संदेश

भनवापुर / सिद्धार्थनगर। भनवापुर ब्लॉक के मंगराव स्थित परिषदीय विद्यालय ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट पहचान स्थापित की है। विद्यालय के दो मेधावी छात्रकृ आनंद पुत्र भगवानदीन एवं मोनी पुत्री विनय कुमारकृका चयन मंडल स्तरीय अटल आवासीय विद्यालय, बस्ती में हुआ है। इस उपलब्धि से विद्यालय, अभिभावकों

और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। शनिवार को विद्यालय परिसर में आयोजित एक सादे सम्मान समारोह में मार्गदर्शक शिक्षक प्रदीप कुमार ने चयनित छात्रों को मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। उन्होंने बताया कि दोनों छात्र अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथ ही उन्होंने

कहा कि मंगराव विद्यालय के छात्र हर वर्ष विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक दुर्गेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष अटल आवासीय विद्यालय में 2 छात्रों के चयन के अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय में 4, सर्वोदय विद्यालय में 10 तथा विद्या ज्ञान



प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में 2 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। सभी चयनित छात्र शीघ्र ही विभिन्न आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस सफलता का श्रेय शिक्षकों की मेहनत, छात्रों की लगन एवं अभिभावकों के सहयोग को दिया।

इस अवसर पर बीईओ महेंद्र कुमार, आबिद रिजवी, ग्राम प्रधान राम विलास, पूर्व प्रधान नीरज, तोताराम, दिलीप कुमार एवं सच्चिदानंद सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

आनंद ने बनाया नया कीर्तिमान

मंगराव विद्यालय के छात्र आनंद पुत्र भगवानदीन ने प्राथमिक स्तर की लगभग सभी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मार्गदर्शक शिक्षक प्रदीप कुमार के अनुसार आनंद ने विद्या ज्ञान (प्रारंभिक), जवाहर नवोदय विद्यालय बांसी, सर्वोदय विद्यालय भानपुर बस्ती तथा अटल आवासीय विद्यालय बस्तीकृसमी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। आनंद का सपना आगे चलकर आईएस अधिकारी बनकर देश व समाज की सेवा करना है। उनके पिता भगवानदीन मुंडई में निजी नौकरी करते हैं और बेटे की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मंगराव विद्यालय की यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समापित शिक्षकों की मेहनत का प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है।

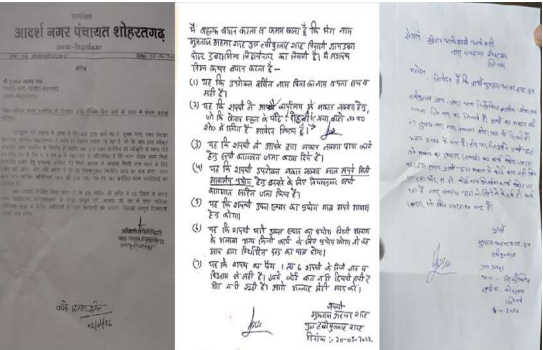
आवासीय नक्शे पर बना मदरसा? ईओ की नोटिस के बाद बढ़ा विवाद सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो से खुला मामला, प्रशासन ने भवन कराया सील

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़ / सिद्धार्थनगर। नगर पंचायत शोहरतगढ़ में एक आवासीय भवन को कथित रूप

के रूप में विकसित किया गया है। वीडियो में वजू के लिए सीमेंटेड बैठका, कई टोटियां और

मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया।



से मदरसा के रूप में तैयार किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अधिशासी अधिकारी (ईओ) अजय कुमार द्वारा 02 अप्रैल को जारी कारण बताओ नोटिस के बाद भवन स्वामी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, वार्ड संख्यादू7 सुभाष नगर स्थित भवन के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह दावा किया गया कि भवन को स्वीकृत मानचित्र के विपरीत मदरसा

शौचालय दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों ने इसे आवासीय भवन के बजाय अन्य उपयोग के रूप में देखा। बताया जा रहा है कि 01 अप्रैल को उक्त स्थल पर उद्घाटन की तैयारी भी की गई थी, जिसमें कुछ बाहरी लोग और महिलाएं भी मौजूद थीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों का विवरण दर्ज किया और उन्हें अगले दिन थाने बुलाया, लेकिन न तो भवन स्वामी उपस्थित हुआ और न ही अन्य लोग पहुंचे।

उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा के निर्देश पर टीम ने मौके का निरीक्षण किया, जहां आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। एहतियातन प्रशासन ने उक्त स्थल को रुकवाकर भवन को बंद करा दिया। जांच के दौरान पते में भी विसंगति सामने आई। शपथ पत्र में जहां ग्राम डबरा (जोगिया ब्लॉक) का पता दर्ज है, वहीं आधार कार्ड में गुजरात के वापी (वलसाड़) का पता होने की बात कही जा रही है। ईओ अजय कुमार द्वारा जारी

किया जा रहा है, जो कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 178, 179 एवं 180 का उल्लंघन है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि भवन का उपयोग केवल निजी आवासीय प्रयोजन हेतु करने का शपथ पत्र दिया गया था। हालांकि, शनिवार को भवन स्वामी मुमताज अहमद शाह ने अपने जवाब में कहा कि भवन का निर्माण वर्ष 2022 में हुआ था और हाल ही में केवल प्लास्टर का कार्य किया जा रहा था,

जिसे नोटिस से पहले ही बंद कर दिया गया। उन्होंने किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अन्य उपयोग से इनकार किया है। वहीं, वर्ष 2022 में दिए गए शपथ पत्र में भवन स्वामी ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि भवन का उपयोग केवल निजी आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उपयोग की स्थिति

तहसील इटवा में सम्पन्न हुआ सम्पूर्ण समाधान दिवस, 26 शिकायतों में 5 का मौके पर निस्तारण

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। तहसील इटवा में सम्पूर्ण तहसील समाधान

एवं उपजिलाधिकारी इटवा कुणाल द्वारा सुनी गई, जबकि

रूप से भूमि विवादों के मामलों को प्राथमिकता देते हुए मौके



दिवस का आयोजन जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में राजस्व, विकास, शिक्षा, पूर्ति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गई। राजस्व व अन्य विभागों की शिकायतें जिलाधिकारी

पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने पिछले समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की आख्या का अवलोकन करते हुए आवश्यक मामलों में जिला स्तरीय टीम गठित कर मौके पर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष

पर निरीक्षण कर त्वरित निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील समाधान दिवस एवं आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि

शिकायतों की जांच शिकायतकर्ता एवं विपक्षी दोनों की उपस्थिति में की जाए। साथ ही कानूनगो एवं लेखपालों को भूमि संपत्ति एवं भूमि विवाद रजिस्टर अनिवार्य रूप से तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी विभाग का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल एवं कानूनगो को निर्देश दिया गया कि निस्तारण से पूर्व मौके का निरीक्षण कर ही आख्या प्रस्तुत करें। समाधान दिवस के दौरान कुल 26 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व के 13, पुलिस के 5, विकास के 2, विद्युत के 3, चक्रबंदी का 1, पूर्ति का 1

तथा समाज कल्याण का 1 प्रार्थना पत्र शामिल रहा। इनमें से राजस्व के 4 एवं समाज कल्याण का 1 प्रकरण मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तीन दिवस के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पीडी नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी महिपाल सिंह, तहसीलदार इटवा सहित क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष, खंड विकास अधिकारी, सीडीपीओ एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, अधिकाधिकवादों के निस्तारण का आह्वान

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 09 मई 2026 (द्वितीय शनिवार) को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार जनपद में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर अरुण कुमार चतुर्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि

उक्त तिथि को प्रातः 10:00 बजे से सिविल कोर्ट सिद्धार्थनगर सहित बाह्य स्थित न्यायालय बांसी, डुमरियागंज, ग्राम न्यायालय इटवा एवं जिला कारागार सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व, चक्रबंदी एवं अन्य न्यायालयों में भी वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित

अधिनियम से संबंधित मामले, न्यायालयों में लंबित पुराने वाद, ई-चालान, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकार, याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित), सेवा संबंधी वेतन विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष आदि) को प्राथमिकता के आधार

पर निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलोंकृ जैसे धारा 138 के प्रकरण, बैंक वसूली, श्रम वाद, विद्युत एवं जल विवाद, पारिवारिक एवं अन्य सिविल मामलोंकृका भी आपसी सुलह-समझौते का आधार पर निपटारा किया जाएगा। ऐसे विवाद जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उन्हें भी वाद पूर्व स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है। सचिव ने सभी संबंधित

विभागों एवं आमजन से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु सक्रिय सहयोग करें, जिससे आपसी सहमति के आधार पर विवादों का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिकाधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का त्वरित निस्तारण करा सकें।

सम्पादकीय

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया पर शुरु से ही नजर बनाये हुए है। चुनाव आयोग भी दावा कर रहा है कि किसी योग्य मतदाता के साथ अन्याय नहीं होगा। इसी मकसद से ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर निगरानी के मकसद से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की थी। लेकिन विडंबना है कि उन्हें ही आक्रोशित भीड़ ने बंधक बनाया। लेकिन इसके बावजूद सरकारी तंत्र ...

टेट विरोध को लेकर संसद से सड़क तक प्रतिरोध तेज



एक फैसला जिसने सरकार को ऊहापोह की स्थिति में ला दिया है। सड़क हो या सदन, सभी जगहों पर न्याय की दरकार लिए हुए प्रतिरोध के स्वर गुंजे हैं। प्रतिरोध का वास्तविक कारण टेट का भूतलक्षी होना है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 अप्रैल 2026 को शिक्षक पात्रता परीक्षा , टेट, की अनिवार्यता के विरोध में एक विशाल महारैली और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि शिक्षक इसे प्काला कानूनग मान रहे हैं क्योंकि यह उनकी सेवा की सुरक्षा और भविष्य पर सीधा प्रहार कर रहा है। टेट विरोध का मुख्य कारण भूतलक्षी प्रभाव है। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद, उन शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया गया है जो कई वर्षों से सेवा में हैं।टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (टी एफ आई) के अनुसार, इस नियम से देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। प्रदर्शन की मुख्य मांगें देखिए। संसद से अध्यादेश पारित कर लाखों शिक्षकों को सेवा सुरक्षा की गारंटी प्रदान करे। शिक्षकों की मांग है कि सरकार संसद में एक अध्यादेश या कानून लाए जिससे सेवारत शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए। ध्यातव्य है कि सेवा सुरक्षा अहम मुद्दा है। कार्यरत शिक्षकों के अनुभव को प्राथमिकता देते हुए उन्हें बिना किसी नई परीक्षा के सेवा में बने रहने दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। रामलीला मैदान में शनिवार को लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। उत्तर प्रदेश (विशेष रूप से नोएडा, मेरठ, जौनपुर, वाराणसी) और देश के अन्य हिस्सों से लाखों शिक्षक दिल्ली पहुंचे हैं। शिक्षकों के इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों का समर्थन प्राप्त है। टीएफआई के आह्वान पर प्राथमिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) जैसे बड़े संगठनों ने इस महारैली को अपना पूर्ण समर्थन दिया है।काबिल ए गौर है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए।दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, क्योंकि कई जिलों से शिक्षक बसों, ट्रेनों और निजी वाहनों से दिल्ली कूच कर चुके हैं।शिक्षकों का कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती।

लेखक विनय कांत मिश्र/दैनिक बुद्ध का संदेश

जब अदालत का यह फैसला आया तो इन्हीं स्त्रियों के बारे में सोचने लगी। अब तक तो इन्हें लगता था कि ऐसे प्रसंगों में कानून उनकी मदद करेगा, लेकिन यह फैसला तो एक तरह से पत्नी को सताने वाले पुरुषों को और ताकत देगा। इस इक्कीसवीं सदी के पच्चीस साल बाद इस तरह की बातें आश्चर्य और दुःख में जरूर डालती हैं। जो माता-पिता न जाने कितने संसाधन लगाकर अपनी बेटियों ...

जो माता-पिता न जाने कितने संसाधन लगाकर अपनी बेटियों को पालते हैं, उन्हें पढ़ाते, लिखाते हैं, उनका विवाह करते हैं, उनकी अच्छी गृहस्थी के सपने देखते हैं, यदि वही लड़की इस तरह से जीवन के थपेड़ों को सहने के लिए पति और कानून द्वारा अकेली छोड़ दी जाएगी, तो इन माता-पिता का क्या होगा। हाल ही में प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा पुरुष, किसी अन्य महिला के साथ लिव-इन में रह सकता है। इस तरह रहना कोई अपराध नहीं है। नैतिकता और कानून को अलग रखना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आवमी से तलाक और मुआवजा ले सकती है। जबकि प्रयागराज हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच ने निर्णय दिया कि वे उन लिव-इन जोड़ों को सुरक्षा नहीं दे सकते, जो पहले से ही शादीशुदा हैं और जिन्होंने तलाक नहीं लिया है। ऐसे जोड़ों के जीवन में दखल देने का अधिकार भी किसी को नहीं है। लेकिन इसे कानूनी मान्यता तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि तलाक न हो।

वास्तव में, परम स्वतंत्रता जैसी चीज कोई नहीं होती। हां, यदि ऐसे जोड़ों को किसी हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वे पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हैं। इसी तरह का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिया था। अदालत ने कहा था कि दो वयस्क अपनी मर्जी से साथी चुन सकते हैं। और साथ रहने का फैसला कर सकते हैं। इन्हें यदि अपने परिवार के लोगों से खतरा है, तो पुलिस सुरक्षा लेने का पूरा अधिकार है। कानून को देखें तो बिना तलाक लिए इस तरह रहने की इजाजत नहीं होती। इसके अलावा बहुत-सी अदालतों ने इसे पति या पत्नी के अधिकारों का उल्लंघन भी माना है। एक जमाने में भारत में बदचलनी (एडल्टरी) को कानूनन अपराध माना जाता था, लेकिन अब वह अपराध नहीं है। लेकिन इसके आधार पर तलाक मिल सकता है।



अक्सर बहुत से सामाजिक मुद्दे कानूनी दांव-पेच में खो जाते हैं।

बहुत से पुरुषों की सोच रहती है कि घर में एक पत्नी है, जो उनके परिवार की जरूरतों और बच्चों के पालन-पोषण के लिए है, लेकिन बाहर घूमने-फिरने, मौज उड़ाने के लिए एक और स्त्री चाहिए। घरवाली बाहरवाली, जैसी फिल्में विगत में सुपरहिट



संवैधानिक संस्थाओं की अग्निपरीक्षा

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावलियों के निस्तारण में लगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। इन सात बंधक अधिकारियों में तीन महिलाएं भी शामिल थीं जिन्हें नौ घंटे तक बिना खाना-पानी के रोके रखा गया। स्वाभाविक रूप से इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी समेत कई उच्च अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पिछले महीने तक साठ लाख में 47 लाख आपतियों का निस्तारण होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संतुष्टि व्यक्त की है। बहरहाल, इसके बावजूद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसका निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। बहरहाल, मालदा का यह घटनाक्रम कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी अग्निपरीक्षा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत तथा चुनाव आयोग ने राज्य में जंगलराज होने की बात कही है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी निर्वाचन अधिकारियों से मारपीट व घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। जाहिर बात है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों में असंतोष है। मतदाता सूची से नाम कटने वाले लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन यह तंत्र के प्रति बढ़ते अविश्वास का भी प्रतीक है, जिसके चलते ही घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में इस माह की 23 व 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मालदा का घटनाक्रम निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनौती दर्शाने वाला है। बहरहाल, मालदा के कालियाचक में भीड़ द्वारा

अभिव्यक्त आक्रोश और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का घटनाक्रम यह बताता है कि लोगों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर व्यापक असंतोष है। यद्यपि कानून व्यवस्था को हाथ में लेना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही घटना का आकलन न कर पाना और समय रहते कार्रवाई न करना, तंत्र की विफलता को ही दर्शाता है। जिसे कानून व्यवस्था की नाकामी ही कहा जा सकता है। जब राज्य में एसआईआर काम में लगे लोगों को पहले से लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था, तो इस कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लोगों में उपजे अविश्वास के मद्देनजर इस दिशा में सतर्क पहल जरूरी थी। इसमें दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर विदेशियों की घुसपैठ की समस्या रही है। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया द्वारा मतदाताओं की पड़ताल राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते व जरूरी कागजों के उपलब्ध न होने से कुछ वैध मतदाताओं को अपनी वैधता की पुष्टि के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चिंताओं को भी समझने की जरूरत है। ऐसे मतदाताओं के अविश्वास को भी दूर करने की जरूरत है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया पर शुरु से ही नजर बनाये हुए है। चुनाव आयोग भी दावा कर रहा है कि किसी योग्य मतदाता के साथ अन्याय नहीं होगा। इसी मकसद से ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर निगरानी के मकसद से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की थी। लेकिन विडंबना है कि उन्हें ही आक्रोशित भीड़ ने बंधक बनाया। लेकिन इसके बावजूद सरकारी तंत्र को लोगों के बीच भरोसा कायम करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास किया जाना चाहिए कि राज्य के राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने के बजाय मतदाताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिये प्रेरित करेंगे। राज्य में स्वतंत्र-निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए राजनेताओं का संवेदनशील व्यवहार जरूरी है।

एलपीजी का विकल्प बन सकती है बायोगैस

वर्तमान वैश्विक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। बायोगैस जैसे स्वदेशी और टिकाऊ विकल्पों को अपनाकर भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को गति दे सकता है। आज जरूरत है एक समन्वित प्रयास की नीतियों, तकनीक और जनभागीदारी के जरिए ताकि ...

वर्तमान वैश्विक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। बायोगैस जैसे स्वदेशी और टिकाऊ विकल्पों को अपनाकर भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को गति दे सकता है। भारत आज ऊर्जा परिवर्तन के एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों घरों तक एलपीजी पहुंचाकर स्वच्छ ईंधन की क्रांति लाई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती आयात निर्भरता, कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

हाल के समय में पश्चिम एशिया के तनाव के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने की घटनाओं ने इस चिंता को और गहरा किया है। अमेरिकादु इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। निःसंदेह, यह स्थिति भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए एक चेतावनी है कि अब ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्न को टालना संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संकटों का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता हैकृपेट्रो-ल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है और घरेलू रसोई तक प्रभावित होती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प तलाशें। इसी

संदर्भ में बायोगैस एक मजबूत और टिकाऊ समाधान के रूप में उभरती है।

बायोगैस जैविक कचरेकृजैसे गोबर, कृषि अवशेष, रसोई कचरा आदिकृसे उत्पन्न गैस है,



जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। यह गैस खाना पकाने, बिजली उत्पादन और वाहन ईं-ान के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बायोगैस की अपार संभावनाएं हैं। गांवों में पशुधुन और जैविक कचरे की उपलब्धता इसे एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है।

गांवों में छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस प्लांट स्थापित कर स्थानीय स्तर पर गैस का उत्पादन किया जा सकता है। इससे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी। आधुनिक तकनीक के माध्यम से बायोगैस को शुद्ध कर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाया जा सकता है, जो

एलपीजी और सीएनजी का प्रभावी विकल्प है। 'गोबर-धन योजना' और 'एसएटीएटी' जैसी योजनाएं बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। इनके माध्यम से किसानों और उद्यमियों को आर्थिक सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस में बदलकर न केवल ऊर्जा पैदा की जा सकती है, बल्कि कचरा प्रबंधन की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है।

भारत में एलपीजी की सालाना खपत लगभग 28–31 मिलियन टन के आसपास है। भारत में एलपीजी का घरेलू उत्पादन लगभग 10–12 एमएमटी प्रति वर्ष है। यानी कुल मांग का केवल 35–40 प्रतिशत ही देश में बनता है। भारत को हर साल लगभग 18–22 एमएमटी एलपीजी आयात करनी पड़ती है। यानी 60–65 प्रतिशत एलपीजी आयात पर निर्भरता। भारत आधा से ज्यादा एलपीजी बाहर से खरीदता है। आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। भारत में अभी लगभग 132 सीबीजी प्लांट चल रहे हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 920 टन प्रतिदिन है। यानी अभी बायोगैस का योगदान 1 प्रतिशत से भी कम है। भारत 20 एमएमटी सीबीजी बना सकता है। कुल संभावित क्षमता कचरा, गोबर, अवशेष की। कुल क्षमता लगभग 60 एमएमटी तक मानी जाती है। इसका मतलब भारत अपनी पूरी

एलपीजी जरूरत (30 एमएमटी) बायोगैस से पूरा कर सकता है। फिलहाल अभी लगभग 300 से अधिक नए प्लांट निर्माणाधीन हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत में 2030 तक बायोगैस उत्पादन 7 गुना तक बढ़ सकता है। बायोगैस न केवल सस्ती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जैविक खाद भी मिलती है और किसानों की आय बढ़ती है। साथ ही, यह स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। हालांकि, बायोगैस के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैंकृजैसे शुरुआती निवेश, तकनीकी जानकारी की कमी और जागरूकता का अभाव। भारत में बायोगैस को लेकर अभी भी कई भ्रांतियां हैं। कई लोग इसे 'गांव की तकनीक' मानते हैं या इसके उपयोग मेंअसुविधा महसूस करते हैं। दूसरी ओर, एलपीजी को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग एलपीजी को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराएं। वर्तमान वैश्विक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। बायोगैस जैसे स्वदेशी और टिकाऊ विकल्पों को अपनाकर भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को गति दे सकता है।

घरवाली-बाहरवाली का त्रास झेलती स्त्री

होती रही हैं। मशहूर हिंदी लेखक स्व. जैनेंद्र कुमार ने तो सतर के दशक में एक प्रस्थापना ही दे डाली थी कि लेखकों को प्रेरणा पाने के लिए पत्नी के अलावा एक प्रेमिका भी चाहिए। उस समय जैनेंद्र जी के इस कथन पर बहुत विवाद भी हुआ था। कई स्त्रियों ने कहा था कि यदि पत्नियां भी ऐसा ही कहने लगें कि उन्हें भी लिखने के लिए पति के अलावा एक और प्रेमी चाहिए, तो क्या होगा।

यह भी सच है कि दवे-छिपे ऐसा होता भी रहता है। बहुत-सी जगह कानून एक तरफ चलता है, और समाज के दवाब दूसरी तरफ। अब भी कई कम्युनिटीज ऐसी हैं, जहां पुरुष कई विवाह कर लेते हैं। कई जगहों पर स्त्रियों को भी यह सुविधा प्राप्त है। यदि हालिया निर्णय के संदर्भ में पढ़ें, शादीशुदा पुरुषों को कानून का सहारा भी मिल जाएगा कि वे किसी और के साथ रह सकें। जो स्त्री किसी की पत्नी है, उसे हमेशा यह डर सताता रहेगा कि कहीं उसका

पति किसी और के साथ रहने चला गया, तो उसका क्या होगा। हर स्त्री के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वह ऐसे मामले में अदालतों के चक्कर लगा सके और न्याय प्राप्त कर सके। यदि इस स्त्री के बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा। पति तो किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया होगा। और क्या मात्र तलाक मिलने या मुआवजा मिलने

से इस तरह से त्यागी गई स्त्रियों का जीवन चल जाएगा। अकेलेपन और अपमान की उस भावना का क्या, जो इन स्त्रियों को झेलनी पड़ेगी। त्यागना या रिजेक्शन एक ऐसी भावना होती है, जो पल-पल सताती है। आज भी बहुत से पुरुषों के मुंह से ये शब्द आसानी से निकलते हैं कि या तो ये कर, वरना तुझे छोड़ दूंगा। जैसे कि किसी स्त्री को छोड़ना उसका मौलिक अधिकार हो। ऐसी रील्स से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कई लोगों को इस बात को बहुत अहंकारपूर्वक कहते भी सुना है कि हां मैं किसी और के साथ रहता हूं। रिलेशनशिप में भी हूं, लेकिन तब भी मेरी पत्नी से पूछो कि क्या उसे किसी तरह की तकलीफ होने देता हूं, पैसे, टके, घर, बार आदि की। बाहर

क्या करता हूं, इससे उसे क्या मतलब। इस तरह की वाक्यावली दरअसल स्त्री को यही बताने के लिए होती है कि वह चाहे कुछ भी कर ले है।आज भी दायम दर्जे की नागरिक। मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में बयान दिया था कि मुसलमानों के मुकाबले हिंदू और सिख पुरुष दो पत्नियां अधिक रखते हैं। सीताराम येचुरी ने तो पूरी किताब ही लिखी

थी। इनके विचारों से हम सहमत न हों, लेकिन अय्यर या येचुरी ने जब यह लिखा, तो इसका मतलब यह भी है कि समाज में एक से अधिक पत्नियां या सम्बंध रखने में बहुत से पुरुष आज भी यकीन करते हैं। भले ही समाज या कानून की नजर में इसे अच्छा न माना जाता हो। कई स्त्रियां भी इन दिनों ऐसा करती पाई जाती हैं, लेकिन उनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है, इसीलिए वे खबर भी बनती हैं। यह भी लगता है कि अब जब अदालत ने पुरुष के शादीशुदा होने पर भी लिव-इन में रहकर दूसरे सम्बंध को रखने की अनुमति दे दी है, तो ऐसे सम्बंधों को बढ़ने से कैसे रोका जा सकेगा।

सिद्धार्थनगर का सबसे बड़ा फ़्रीटींग पब्लिकेशन हाउस...
किस्कीभीलपढ़ेंऔरअपनीकड़ीआइएँ

बुद्ध पब्लिकेशन
ऑफ़सेट एण्ड प्रिन्टर्स

जी.एस.टी. श्रिल बुक/फ़ार्म
कार्यालय ऑफ़सेट
स्कूल कॉपी/फ़ार्म/अयर्स
फ़पलेट
कलर पोस्टर
कलर डिप्लिमा कार्ड
डिजिटल लेट-पेज
बैंक फ़ार्म
लिकट-टीरो एजेंन्सी. बीगड मधकरपुर-सिद्धार्थनगर (उ.प्र.)
☎ 8795951917, 9453824459

Email: info@buddhakasandesh.com
 Website: www.budhakasandesh.com
 Address: Gt. Budhakasandesh, Varanasi-221002



